मुख्यमंत्री के फैसलों से कर्मचारी संतुष्ट, जताया आभार

कर्मचारी राज्य की महत्वपूर्ण कड़ी, उनकी समस्या का समाधान करना हमारी प्राथमिकता : भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरूवार को कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के साथ बजट से पहले ने संवाद किया।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से गुरूवार को उनके कार्यालय में संवाद करने आये कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों ने एक सुर में मुख्यमंत्री का बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी की घोषणाओं, जमीन पर उनका शीघ्र क्रियान्वयन तथा कर्मचारियों के हितों में लिए जा रहे निर्णयों के लिए आभार व्यक्त किया। कर्मचारी संगठनों ने कहा कि कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री की

- **'विकसित राजस्थान के लक्ष्य के लिए समर्पण भाव से काम करें कार्मिक'**

नीयत और नीति अच्छी है। आज कर्मचारी बहुत खुश हैं तथा मुख्यमंत्री द्वारा लिए जा रहे निर्णयों से उनमें संतोष का भाव है। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की समस्याओं को जानने के लिए आमंत्रित कर निरन्तर संवाद किया है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि मंत्री एवं विभागीय स्तर पर भी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी हमारे राज्य की महत्वपूर्ण कड़ी है तथा सरकार और कर्मचारी का संबंध प्रगाढ़ होता है। हमारी प्राथमिकता है कि कर्मचारियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा कि विकसित और खुशहाल राजस्थान के लक्ष्य के लिए कार्मिक समर्पण एवं सेवाभाव के साथ काम करें तथा आगामी बजट 2025-26 में कर्मचारी संगठनों से प्राप्त सुझावों को परीक्षण कर यथासंभव शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य की 8 करोड़ जनता की आशा और आंकाक्षाओं को पूरा करने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि गत एक वर्ष में राज्य सरकार ने राज्य में बिजली-पानी की प्राथमिकता को समझते हुए अनेक निर्णय लिए हैं। ईआरसीपी, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना सहित विभिन्न परियोजनाओं से जहां राज्य में जल की आपूर्ति बढ़ी हैं, वहीं किसानों को 2027 तक दिन में बिजली देने के लक्ष्य को लेकर राइजिंग राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वाधिक एमओयू किए गए हैं। राज्य सरकार प्रदेश को उत्कृष्ट और विकसित राजस्थान बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही है।

बैठक में कर्मचारियों द्वारा वेतन विसंगति, ग्रेड-पे, पदोन्नित अवसरों का पर्याप्त सृजन, संविदाकर्मियों का नियमितीकरण, दिव्यांगों को आरक्षण, कर्मचारियों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट सहित विभिन्न विषयों पर अपनी राय रखी। बैठक में पंचायती राज, शिक्षा, मेडिकल, सचिवालय सेवा, मंत्रालयिक सेवा, कार्मिक, आंगनबाड़ी, जलदाय विभाग, पटवारी सेवा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, कृषि सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव दिए।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) आलोक गुप्ता सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

पी.टी.आई. के बर्खास्तगी नोटिस मामले में स्टे लगाया

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती के आवेदन पत्र में मिस मैच से जुडे मामले में याचिकाकर्ता पीटीआई के बर्खास्तगी नोटिस पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार के शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव सहित अन्य पक्षकारों से जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश महिमा कुमारी व अन्य की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 16 जून 2022 को पीटीआई के 5546 पदों पर भर्ती निकाली थी। इसमें चयन का आधार लिखित परीक्षा थी। याचिकाकर्ताओं ने भर्ती का आवेदन पत्र ऑनलाइन भरा था, लेकिन आवेदन पत्र में ई मित्र संचालकों ने बीपीएड परीक्षा के रोल नंबर की जगह गलती से एनरोलमेंट नंबर भर दिया।

फरवरी से फार्मर रजिस्ट्री प्रदेशभर में शुरू होगी : मुख्यमंत्री

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि एग्रीस्टैक किसान केन्द्रित समाधान उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वाकांक्षी पहल है एवं इससे कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की शुरूआत होगी। इसके अन्तर्गत किसानों की जानकारी का व्यापक डाटाबेस तैयार करते हुए प्रत्येक किसान को विशिष्ट फार्मर आईडी प्रदान की जाएगी। इससे किसानों को केन्द्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सुगमता एवं पारदर्शिता आएगी।

- **'एग्रीस्टैक से कृषि में होगी डिजिटल क्रांति की शुरूआत'**
- **चरणबद्ध रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप आयोजित होंगे**

शर्मा गुरूवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में एग्रीस्टैक योजना एवं फार्मर रजिस्ट्री रोल-आउट को लेकर समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में एग्रीस्टैक परियोजना को लेकर मिशन मोड़ पर कार्य किया जाए एवं इससे जुड़ने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर दिसम्बर में सीकर जिले से इस मिशन को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया। आगामी फरवरी माह से इसे प्रदेशभर में शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत चरणबद्ध रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री के लिए कैम्प लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इन कैम्पों को लेकर तैयारी पूरी करने तथा तथा उपखंड स्तर पर पर्यवेक्षण एवं जिला स्तर पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कैम्पों में आमजन को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। साथ ही, इन कैम्पों में अन्य विभागों की संबंधित सेवाओं को भी शामिल किया जाए।

शर्मा ने कहा कि इस मिशन में किसान अहम कड़ी हैं। उनको इस मिशन के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। जिससे वे इससे जुड़ें और प्रदेश के प्रत्येक किसान को योजनाओं का लाभ मिल सके और कोई भी अन्नदाता सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे। बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोडा, अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव राजस्व दिनेश कुमार, प्रमुख शासन सचिव सहकारिता मंजू राजपाल सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

शपथ लेना सरल मगर इसको निभाना कठिन : देवनानी

जयपुर। विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राज्य कर्मचारियों का आव्हान किया है कि वे ईमानदारी व निष्ठा और संवेदनशीलता से कार्य कर राज्य सरकार के जनहितकारी सकल्पों को पूरा करने में सक्रिय भागीदारी निभाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी समय पर आए, समय पर जाए और जनहित के कार्य कर राजस्थान की माटी को यश दिलाएं। देवनानी गुरुवार को यहा जयपुर कलेक्ट्रेट में नव निर्वाचित राजस्व मंत्रालयिक संघ की कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। देवनानी ने सभी कर्मचारियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कर्म और भाग्य हमारे जीवनरुपी लॉकर की दो चाबियां हैं। राज्य हित में राजकीय कार्यों का ईमानदारी व निष्ठा से सम्पादन आवश्यक है।

युवा कांग्रेस ने बनाए विधानसभा प्रभारी

जयपुर। राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस ने प्रदेश संयोजक बनाकर 96 विधानसभा में प्रभारी नियुक्त किए हैं। अन्य सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी भी जल्द नियुक्त किए जाएंगे।

यह नियुक्ति प्रदेश प्रभारी मोहम्मद शाहिद के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया की अनुशंसा तथा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुधींद्र मूंड, यशवीर शूरा के सहमति से संगठन प्रभारी अरबाब खान ने की है।

प्रत्येक विधानसभा प्रभारी की जिम्मेदारी संगठन की विधानसभा कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी, नगर, वार्ड, पंचायत, ग्राम तथा बूथ की कार्यकारिणी को पूरा करना होगा। यह सभी कार्य प्रदेश नेतृत्व की निगरानी में किया जाएगा।

'मुख्यमंत्री प्रदेश के प्रत्येक घर में पानी पहुंचाने के लिए प्रयासरत'

जयपुर। विधायक कुलदीप धनखड ने प्रदेश के समाज सेवियों और भामाशाहों से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे 'कर्मभूमि से मातृभूमि जन भागीदारी जल संचय' के अभियान में जुड़ने का आव्हान किया है। राज्य सरकार इस अभियान से प्रदेश की हर ग्राम पंचायत को जोड़ेगी और हर पंचायत में चार-चार रिचार्ज वाटर शाफ्ट बनाए जाएंगे।

धनखड़ ने कहा कि देश और दुनिया में पानी की उपलब्धता बहुत बड़ा संकट है। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जल से जुड़ी समस्या के स्थाई समाधान के लिए नदियों को जोड़ने की ईआरसीपी परियोजना लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री के नेतत्व में हमारी सरकार प्रदेश के प्रत्येक घर में पानी पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। धनखड़ ने कहा कि प्रदेश के कांग्रेस के नेता लगातार अनर्गल वक्तव्य देकर हमारी सरकार पर आरोप लगाते हैं।

राहुल गांधी की निष्ठा भारत के प्रति नहीं : मदन राठौड़

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के गैर जिम्मेदाराना बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की शपथ ली है, लेकिन उनके बयान से यह स्पष्ट हो गया कि उनकी निष्ठा भारत के प्रति नहीं है। उनकी गतिविधियां और उनके बयान राष्ट्र हित में नहीं है। राहुल गांधी की भारत की बजाए इटली के प्रति निष्ठाएं उजागर हो रही है। भारत स्टेट के खिलाफ बयान देने वाले राहुल गांधी या तो शब्दों का चयन सही नहीं कर पा रहे है या फिर उनके अन्तकरण में जो भाव हैं, वो खुलकर सामने आ रहे हैं।

गेहूं खरीद की तैयारियों को प्रह्लाद जोशी ने सराहा

जयपुर। प्रदेश में गेहूं की खरीद समर्थन मूल्य पर करने को लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। विभाग के मंत्री सुमित गोदारा की ओर से बार बार अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि किसी भी किसान को रजिस्ट्रेशन या अन्य किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके लिए विभागीय अधिकारी हर वक्त मुस्तैद रहें। गेहूं खरीद की तैयारियों को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने पांच राज्यों के मंत्रियों की बैठक ली। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई इस बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा की ओर से राज्य सरकार की ओर की गई तैयारियों की जानकारी दी। इस दौरान विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने राजस्थान की तैयारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राजस्थान की तरह अन्य राज्यों को भी समय रहते पूरी तरह मुस्तैद हो जाना चाहिए ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो।

मंत्री गोदारा ने कहा राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां गेहूं की खरीद देश में सबसे ऊंची दर पर किया जा रहा है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की ओर से किसानों को बड़ी सौगात दी जा रही है। समर्थन मूल्य के अतिरिक्त प्रति क्विंटल 125 रुपए का बोनस दिया जा रहा है। गोदारा ने बताया कि गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल है लेकिन राजस्थान के किसानों को बोनस सहित 2550 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।

मंत्री सुमित गोदारा ने जानकारी दी कि गेहूं की खरीद एफसीआई, राजफैड, तिलम संघ, नेफेड और एनसीसीएफ की ओर से की जाएगी। प्रदेशभर में कुल 259 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इनमें एफसीआई के 153, राजफैड के 15, तिलम संघ के 45, नैफेड के 15 और एनसीसीएफ के 31 खरीद केंद्र शामिल हैं।

समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद 10 मार्च से 30 जून तक होगी। गेहूं बेचने के लिए किसानों राज्य सरकार द्वारा जारी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 जनवरी से शुरू हो चुकी है जो कि 25 जून तक चलेगी। ना केवल दिन के समय बल्कि किसान 24 घंटों में कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बुधवार तक करीब 14 हजार किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान अगर किसी किसान भाई को किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6030 पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल करके अपनी समस्या का निराकरण करा सकते हैं।